'हर साल होगा राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव का आयोजन'

मुख्यमंत्री ने मसालों की प्रोसेसिंग, मार्केटिंग व निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए यह घोषणा की

जयपुर, 8 सितंबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को जयपुर के बिड़ला सभागार में आयोजित "राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव-2025" का भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि अब यह आयोजन हर वर्ष किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मसालों के क्षेत्र में

- **मुख्यमंत्री भजनलाल ने जोधपुर के आंगणवा में तथा टोंक के सोहेला में स्थापित इन्क्यूबेशन सेंटर्स का वर्चअल लोकार्पण किया।**

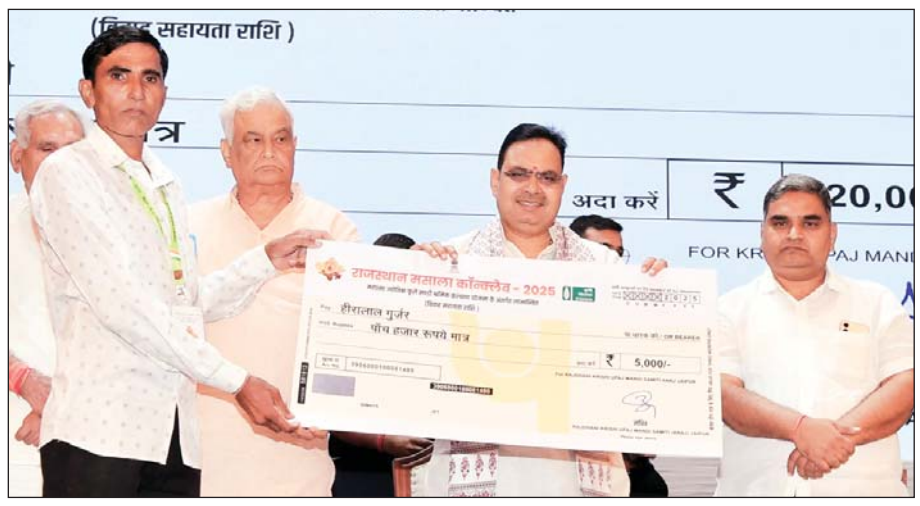

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के बिड़ला सभागार में "राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव-2025" का शुभारंभ किया और एफपीओ पंजीयन प्रमाण पत्र, श्रम सम्मान कार्ड, मसालों से जुड़ी योजनाओं के फोल्डर और कृषि विपणन योजनाओं के चैक भी वितरित किए गए।

राजस्थान की समृद्ध परंपरा और उत्पादन क्षमताएं इसे देश और दुनिया में विशिष्ट स्थान दिलाती हैं। यह कॉन्क्लेव किसानों, उत्पादकों और व्यापारियों को एक वैश्विक मंच उपलब्ध कराएगा।

मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि राजस्थान देश में जीरा उत्पादन में प्रथम, मेथी और सौंफ में द्वितीय तथा धनिया और अजवाइन उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि मसालों के क्षेत्र को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रसंस्करण, विपणन और निर्यात के क्षेत्रों में सरकार द्वारा ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जोधपुर के आंगणवा और टोंक के सोहेला में स्थापित इन्क्यूबेशन सेंटर्स का वर्चुअल लोकार्पण किया। इसी के साथ टोंक जिले के सोनवा में फूड पार्क का भी उद्घाटन किया गया।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज-स्पाइस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया और एफपीओ पंजीयन प्रमाण पत्र, श्रम सम्मान कार्ड, मसालों से जुड़ी योजनाओं के फोल्डर और कृषि विपणन योजनाओं के चेक भी वितरित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि खाद और बीज की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इस आयोजन में सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक, शासन सचिव कृषि राजन विशाल सहित बड़ी संख्या में कृषक, मसाला व्यापारी और कृषि विशेषज्ञ उपस्थित रहे।

"आधार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सुप्रीम कोर्ट बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।

राज्य में विपक्ष, जिसमें कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल शामिल हैं और जो महागठबंधन का हिस्सा हैं, ने तर्क दिया है कि यह पुनरीक्षण लाखों ऐसे पुरुषों और महिलाओं को मताधिकार से वंचित करने की साज़िश है, जो परंपरागत रूप से उनके पक्ष में मतदान करते हैं। कांग्रेस ने यहाँ तक आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर वोटर लिस्ट में धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं।

हालाँकि, चुनाव आयोग ने ज़ोर देकर कहा है कि उसका गहन पुनरीक्षण कानूनी और संवैधानिक दायरे में है और मतदाता दोबारा सत्यापन की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की गई है।

संघ के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले कोर कमेटी के कुछ सदस्यों के साथ यहीं रुके हुए हैं। सोमवार दोपहर दो बजे के करीब होसबोले की तबीयत बिगड़ गई। तत्काल उनको एम्स में भर्ती करवाया गया। सूचना पर बाड़मेर के पूर्व सांसद मानवेन्द्र सिंह जसोल, आरएसएस जोधपुर प्रांत के विद्यानंद भाईसाहब, कलेक्टर गौरव अग्रवाल और कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान भी एम्स पहुंचे। होसबोले आरएसएस में मोहन भागवत के बाद दूसरे सबसे बड़े पदाधिकारी हैं।

जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बीआरएस (चार सांसद) और बीजद (सात सांसद) का रुख़ अभी स्पष्ट नहीं है। बीआरएस पार्टी प्रमुख केसीआर की बेटी के. कविता के इस्तीफ़े और भाजपा व कांग्रेस दोनों के खिलाफ़ आक्रामक रुख़ के कारण बी आर एस में आंतरिक उथल-पुथल चल रही है, इसलिए उसके चुनाव से दूर रहने की संभावना है। इसके अलावा, बीआरएस की नज़र जुबली हिल्स विधानसभा सीट के उपचुनाव पर भी है, जहाँ मुस्लिम वोट अहम माने जाते हैं। यह सीट मगन्ती गोपीनाथ ने 2018 और 2023 में बी.आर.एस. के लिए जीती थी, गोपीनाथ की जून में मृत्यु हो गई।

बीजू जनता दल (बीजद) से समर्थन की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन उसने अब तक औपचारिक घोषणा नहीं की है। माना जा रहा है कि वह अब भी असमंजस में है, क्योंकि पिछले साल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उसे कड़ी टक्कर दी थी।

इसके बावजूद, बीआरएस और बीजद का समर्थन नहीं मिलने पर भी एनडीए के पास 436 वोट होंगे और यह संख्या और भी बढ़ सकती है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल भी इस चुनाव में एक दिलचस्प पहलू हैं। पिछले साल उनका अपनी ही पार्टी से रिश्ता उस समय टूट गया था, जब उन्होंने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी पर शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था। तब से उनके आप को छोड़ देने तथा भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगाई जाती रहीं, लेकिन उन्होंने न तो अपने पद से इस्तीफ़ा दिया और न ही पार्टी बदली। इससे चुनाव और रोचक हो गया है। इसके अलावा, लोकसभा के सात निर्दलीय सांसदों के बारे में भी अनिश्चितता की स्थिति है। इसी तरह अकाली दल और मिज़ोरम की ज़ेडपीएम का भी रुख़ साफ़ नहीं है, जिनमें से प्रत्येक के एक-एक सांसद हैं।

- **पर, बी.आर.एस. व बी.जे.डी. के समर्थन के बिना भी एन.डी.ए. को 436 वोट मिलने की संभावना।**
- **आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालिवाल भी केजरीवाल के खिलाफ हैं, जब से केजरीवाल के नुमाइन्दे ने उस पर राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिलवाने का भारी दबाव डाला था।**
- **परन्तु, अगर ये सभी पार्टियां, इण्डिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करती भी हैं, तो भी इण्डिया गठबंधन को जीतने के लिए सत्तर वोट कम पड़ेंगे।**
- **इस सत्य से विपक्ष भी अनभिज्ञ नहीं, पर विपक्ष का मानना है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में अगर उनका प्रदर्शन ठीक रहे, और चुनाव में विपक्ष की एकता बरकरार रही, तो इस माहौल का लाभ इस वर्ष व अगले वर्ष, बिहार, बंगाल व तमिनलाडु के विधानसभा चुनाव में मिलेगा।**

अगर ये सभी वोट राधाकृष्णन के पक्ष में पड़ते हैं, तो भाजपा उम्मीदवार 458 वोट तक पहुँच सकते हैं। यह संख्या तीन साल पहले धनखड़ को मिले 528 वोटों से काफी कम होगी, लेकिन जीत के लिए पर्याप्त रहेगी। विपक्षी खेमे में, कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोनों सदनों को मिलाकर, काग़ज़ पर विपक्ष के पास 324 वोट हैं।

इस बार चुनाव 2022 की तुलना में कड़ा दिख रहा है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के चलते विपक्ष के पास ज्यादा सांसद हैं।

लेकिन फिर भी उनकी जीत की संभावना लगभग "नहीं" के बराबर है। अगर विपक्ष के सारे सांसद वोट डालें और सभी न्यायमूर्ति रेड्डी के पक्ष में वोट दें, तब भी उन्हें 100 से 135 वोट कम ही मिल पायेंगे। यह स्थिति तब भी नहीं बदलेगी, यदि बीआरएस, बीजद, स्वाति मालीवाल, सभी निर्दलीय, एक-सांसद वाली पार्टियाँ और यहां तक कि वाईएसआर कांग्रेस भी विपक्ष के साथ चली जाएं। तब भी इंडिया ब्लॉक के करीब 70 वोट कम रह जाएंगे। स्थिति और भी कठिन इसलिए हो गई है, क्योंकि एनडीए के सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि उन्हें सिर्फ़ राज्यसभा में ही कम से कम 150 क्रॉस वोट की उम्मीद है। इंडिया ब्लॉक पहले ही मान चुका है कि वह यह चुनाव जीतने की उम्मीद नहीं कर रहा। सूत्रों का कहना है कि यह चुनाव कराना विपक्ष की रणनीति का हिस्सा है-ताकि विपक्ष पिछली बार के उपराष्ट्रपति चुनाव की तुलना में अपनी अतिरिक्त ताक़त दिखा सके और आने वाले विधानसभा चुनावों (जिनमें बिहार, बंगाल और तमिलनाडु शामिल हैं) से पहले गति पकड़ सके।

'वो बात सारे फसाने में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नकल करके पास हुए अभ्यर्थियों से अलग करना असंभव है। इस रोचक मामले की सुनवाई के दौरान ही ना तो राज्य सरकार और ना ही प्रतिवादी पक्ष, जो परीक्षा को रद्द करने के पक्ष में नहीं था, ने याचिकाकर्ता पर अंगुली उठाई और कहा कि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई एसआईटी रिपोर्ट वास्तविक नहीं है। उल्लेखनीय है कि राफेल खरीद के मामले के दौरान भी यशवंत सिन्हा और हिंदू अखबार के संपादक व चेयरमैन रह चुके एन. राम पर आरोप लगे थे कि, उन्होंने राफेल की खरीद के संबंध में दस्तावेज जो अदालत में प्रस्तुत किए थे, वह डिफेंस मिनिस्ट्री से चुराए हैं और इन दस्तावेजों को सार्वजनिक करने से भारत की अखंडता व सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। इस मामले में केन्द्र सरकार द्वारा यह भी जिरह की गई थी कि, राफेल की खरीद, उसके दाम और इसकी विशिष्टता विभागीय गोपनीय दस्तावेज हैं, जिसकी चोरी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि, दस्तावेज जहां से भी लाए गए हों, परंतु जनहित में इन्हें अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि, एस.आई.भर्ती-2021 में राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ के समक्ष प्रस्तुत जिस एसआईटी रिपोर्ट पर इतना बवाल खंडपीठ खड़ा कर रही है। उस रिपोर्ट को अब तक ना तो कभी एस.ओ.जी. ने झूठा बताया और ना ही राज्य सरकार ने इस पर कोई सवाल खड़े किए। इनके अलावा प्रतिवादी पक्ष ने भी कभी इसे चुनौती नहीं दी तो आखिर अब खंडपीठ इसकी वास्तविकता का प्रश्न क्यों किस के आधार पर उठा रही है? इस मामले को जानने वाले सूत्रों का कहना है कि, अगर इस मामले की सुनवाई अगली तारीख 8 अक्टूबर को नहीं हुई और स्टे जारी रहा तो इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी जा सकती है।

कई देशों में "जैनरेशन ज़ी" का असंतोष ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है, "हैरानी की बात यह थी कि हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा कोई झंडा-बैनर या पहचान नहीं दिखी।"

काठमांडू की गंभीर स्थिति को देखते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आनन-फानन में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई।

संकट की समीक्षा के लिये संध्या को मंत्रिपरिषद और सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई।

काठमांडू के कई हिस्सों में झड़पों के बाद दिनभर का कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। ताज़ा जानकारी के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के गेट को क्षतिग्रस्त कर दिया है क्योंकि प्रदर्शन हिंसक हो गया था।

स्थिति तब और बिगड़ गई, जब प्रदर्शनकारियों ने प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमाएं तोड़ दीं और संसद भवन के परिसर में घुस गए। पुलिस ने जवाब में वॉटर कैनन, आंसू गैस का प्रयोग किया और फायरिंग की, जिससे कई लोग घायल हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कम से कम 42 लोग घायल हुए हैं।

सरकार ने कहा कि जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक किया गया है, वे सरकार के साथ पंजीकरण नहीं करवा रहे थे। इन प्लेटफॉर्म्स के दुरुपयोग पर नाराजगी जताते हुये सरकार ने कहा कि फर्जी आईडी का उपयोग करके नफरत फैलाना, अफवाहें उड़ाना, साइबर क्राइम करना और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए किया जा रहा था, वास्तविकता यह है कि देश की 3 करोड़ आबादी का 90 प्रतिशत हिस्सा इंटरनेट का उपयोग करता है।

सबसे पहले न्यू बानेश्वर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में लगाये गये कफ्यू को, प्रदर्शनकारियों के प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर जाने के बाद, कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है और इसमें राष्ट्रपति निवास (शीतल निवास), महाराजगंज, उपराष्ट्रपति निवास (लैनचौर), सिंगदरबार का पूरा क्षेत्र, प्रधानमंत्री निवास (बालुवाटार) और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं।

फायरिंग के बाद, गृहमंत्री रमेश लेखक, जो उस समय एक संसदीय समिति की बैठक में थे, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत बैठक से बाहर निकल आए। न्यू बानेश्वर में गोलियां चल रही थीं, और जैसे ही उन्हें सूचना मिली, उन्होंने आपात बैठक बुलाने की जरुरत बताई।

पीलीभीत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कोई पुष्टि नहीं की है। डीएम पीलीभीत ने बताया कि पीलीभीत से नेपाल के बीच व्यापारिक संबंध होने के कारण यहां के परिवार बड़ी संख्या में नेपाल के महेंद्र नगर में ही निवास करने के साथ व्यापार भी करते है। बड़ी संख्या में वहां की नागरिकता भी उन्होंने ले रखी है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908